भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3216
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

ग्रामीण भारत के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी

3216. श्री राहुल कस्वांः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने की सरकार की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में, विशेष रूप से चूरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक इंटरनेट से जुडे गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कई क्षेत्रों में उक्त योजना के कार्य को पूरा करने में किसी विलंब की सूचना मिली है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट चरण-I और चरण-II के अंतर्गत कुल 2,22,341 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिनमें से 2,14,921 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों तथा करीब 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गाँवों को मांग के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

(ग) राजस्थान में चूरू लोकसभा क्षेत्र की 349 ग्राम पंचायतों सहित कुल 8,776 ग्राम पंचायतें भारतनेट के अंतर्गत सेवा के लिए तैयार हैं।

(घ) संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) लागू किया जा रहा है और राजस्थान सहित चौबीस राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को कार्य सौंप दिया गया है। कार्यान्वयन के दौरान मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की स्वीकृति तथा ग्राम पंचायतों में एबीपी उपकरणों के लिए अलग बिजली कनेक्शन की व्यवस्था जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा बीएसएनएल (एबीपी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी) संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

*****